



राष्ट्रीय

छात्रशक्ति

वर्ष 2 ■ अंक 4 ■ जुलाई 2018 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 32



अभाविप नई दृष्टि नया स्वरूप



उच्च शिक्षा का बेहतर
विकल्प है दूरस्थ माध्यम

12

MAKE EDUCATION
SYSTEM
TRANSPARENT AND
QUALITATIVE

11

अंधेरे में
“पूनम का चांद” हैं गुरु

24

प्रदर्शन



खूंदी में हुए सामूहिक दुराचार के विरुद्ध राजभवन, रांची में प्रदर्शन करते अभाविप कार्यकर्ता



मंदसौर की घटना के खिलाफ प्रदर्शन करते अभाविप कर्नाटक के कार्यकर्ता



राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

वर्ष 2, अंक 4
जुलाई, 2018

संपादक

आशुतोष भटनागर

संपादक-मण्डल :

संजीव कुमार सिन्हा

अवनीश सिंह

अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,

नयी दिल्ली - 110002.

फोन : 011-23216298

chhatrashakti.abvp@gmail.com

www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti

www.twitter.com/chhatrashakti1

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक राजकुमार शर्मा द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।



05

अभाविप : नई दृष्टि नया स्वरूप

1990 के वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। शिक्षा का क्षेत्र भी...

संपादकीय	04
'सेल्फी विद कैम्पस' के माध्यम से डेढ़ लाख परिसर तक पहुंचेगी अभाविप	10
Make Education System Transparent and Qualitative	11
उच्च शिक्षा का बेहतर विकल्प है दूरस्थ माध्यम	12
Divisive Politics Hindrance to Development of Nation	17
US-North Korea Relations: History in Making ?	18
Review & Immediate Execution of Scholarships: Need of Hour	20
एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अभाविप का प्रदर्शन	21
खूटी में सामूहिक दुराचार के विरोध में अभाविप का आक्रोश मार्च	21
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय से प्रणव दा के सन्देश का निहितार्थ	22
अंधेरे में "पूनम का चांद" हैं गुरु	24
CONSISTENT EFFORTS NECESSARY FOR WOMEN DIGNITY	26
शहरी नक्सलियों का खतरा	27
सोशल मीडिया पर बढ़ता अमर्यादित भाषा का प्रयोग	29

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय



केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री श्री सत्यपाल सिंह ने एक बार फिर चार्ल्स डार्विन के विकासवाद को नकारते हुए यह विश्वास प्रकट किया कि उनके पूर्वज बंदर नहीं थे। कुछ महीने पहले भी उन्होंने यह बात कही थी जिसके बाद वैज्ञानिक बुद्धि से विभूषित अनेक लोगों ने उनकी आलोचना की थी।

दुर्भाग्य यह है कि एक ऐसे विचार को, जो न तथ्यों पर ठहरता है और न तर्कों पर, भारत में पत्थर की लकीर की तरह स्थापित कर दिया गया। मैकाले के वारिसों के लिये इससे आगे सोच पाना भी संभव नहीं था। आर्यों के भारत पर आक्रमण की बात हो अथवा वेदों के गड़रियों के गीत होने दावा, सभी विचार इस सिद्धांत की ही उपज हैं कि भारत कोई ऐतिहासिक संस्कृति-संपन्न राष्ट्र नहीं बल्कि जड़ और जाहिल लोगों की एक ऐसी भीड़ थी जिसमें 'काफिले बसते रहे और हिन्दोस्तां बनता गया'।

भारत में स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षा-क्षेत्र में वही विचार और वही तौर-तरीके जारी रहे जिन्हें अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। बीच में ऐसे कुछ काल-खण्ड अवश्य आये जब इस धारा से अलग लोग सत्ता में आये। शिक्षा विभाग, जो बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहलाने लगा, भी समय-समय पर ऐसे लोगों के पास रहा जो भारतीयता के हामी थे। लेकिन इसके बाद भी शिक्षा परिदृश्य में सात दशकों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं दिखाई देता है।

सत्ता बदलने से पाठ्यक्रम बदलें, यह निस्संदेह अस्वीकार्य है। किन्तु यह आवश्यक है कि नयी पीढ़ी को सच से अवगत कराया जाय। भारत की ज्ञान परम्परा तो अपने ही नहीं, चार्ल्स डार्विन के पूर्वजों को भी बंदर मानने को तैयार नहीं। किन्तु यह भी सत्य है कि राखीगढ़ और बरनावा के उत्खनन से प्राप्त होने वाले पुरातात्विक साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि डार्विन के पूर्वज ईसा से तीन हजार वर्ष पहले जब सच में वस्त्रहीन रहते थे और बंदरों की तरह ही जंगलों में उछल-कूद किया करते थे, उस समय भारत में रथों का निर्माण हो चुका था और एक विकसित सभ्यता विद्यमान थी।

भारत के अकादमिक जगत में भारतीय ज्ञान एवं मूल्यों की उपेक्षा को ही आधुनिकता और वैज्ञानिकता का प्रतिमान बना दिया गया। परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम में वे सभी बातें जोड़ दी गयीं जो विद्यार्थी को उसकी जड़ों से काटती थीं। इतिहास के वे गौरवशाली पल, जो नयी पीढ़ी में आत्मविश्वास भर सकते थे, पाठ्यक्रम में स्थान नहीं पा सके। बौधायन की प्रमेय पाइथागोरस के नाम हो गयी और कालिदास भारत के शेक्सपियर हो गये।

अंधकार युग से अपने इतिहास का प्रारंभ करने वाले पश्चिम ने भारत में भी एक काल्पनिक अंधकार युग की सृष्टि की। यह उनकी सफलता ही है कि वे अंधकार युग की कपोल-कल्पना का विश्वास उस ऐतिहासिक राष्ट्र के बौद्धिक नेतृत्व को दिलाने में सफल रहे जिसका उद्घोष ही 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' है।

राष्ट्रीयता के उभार के इस कालखण्ड में आवश्यक है कि भारत के सांस्कृतिक सत्य पर विमर्श विश्वविद्यालयों के परिसरों में पहुंचे। जरूरत विमर्श को अंतिम परिणति तक पहुंचाने की है जिसके लिये गंभीर प्रयास के साथ ही राजनैतिक संकल्प का भी प्रदर्शन करना होगा।

नये सत्र में कार्यकर्ता जब परिसरों में जायेंगे तो यह, और इस जैसे अनेक बिन्दु चर्चा के लिये उनके सामने होंगे। समग्र जानकारी के साथ किया गया संवाद सदैव नये विमर्श को जन्म देता है। परिसरों में भारतीयता को प्रकट करने वाले विषय विमर्श के बिन्दु बनें, यही उपयुक्त है।

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना सहित,

आपका
संपादक

अभाविप : नई दृष्टि नया स्वरूप



1990 के वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अप्रभावित नहीं रहा। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में नयी-नयी संकल्पनाओं जैसे मुक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, सेमेस्टर प्रणाली, ट्राइमेस्टर प्रणाली, कम्प्यूटर आधारित शिक्षा, शिक्षक छात्र सम्बन्ध, वर्चुअल क्लास रूम आदि का चलन बढ़ा है। ऐसे में इन परिवर्तनों के बीच अभाविप अपने को **Most Updated and Relevant Organization** बनाने के लिए सतत चिंतनशील रहती है। अभाविप द्वारा अपने कार्य को गतिमान बनाने हेतु महाविद्यालय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इकाई का गठन किया जाता है।

। के. एन. रघुनंदन।

आ

ज शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी में, सामाजिक मान्यताओं में, जीवन पद्धति आदि में तेजी से बदलाव आया है। इन बदलावों ने सर्वाधिक किसी वर्ग को प्रभावित किया है तो वह है देश का युवा वर्ग। इसलिए युवा को परिवर्तन के पर्याय के रूप में देखा जाता है। समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में आ रहे बदलावों के प्रति युवाओं की रचानात्मक भूमिका हेतु अभाविप सदैव सचेष्ट व जागरूक रही है। इसीलिए प्रत्येक पांच वर्ष बाद अभाविप की विचार बैठक होती है। इस विचार बैठक में स्वयं को युगानुकूल बनाने हेतु हम चिन्तन-मंथन करते हैं।

विद्यार्थी परिषद के बारे में एक सामान्य धारणा है कि यह शैक्षिक समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाला एक छात्र संगठन है। परंतु ABVP के बारे में यह एकांकी विचार है। दुनिया के छात्र संगठनों के इतिहास



को हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि अधिकांश का उदय किसी घटना या परिस्थितिवश हुआ है। उस परिस्थिति के समाप्त होने के साथ ही वह छात्र संगठन भी अप्रासांगिक हो जाता है। परन्तु काल के प्रवाह के साथ अभावपि ने अपनी प्रासांगिकता को सतत प्रमाणित किया है, इसके पीछे मूल कारण इसका वैचारिक अधिष्ठान है। इसीलिए हम कहते हैं कि अभावपि एक वैचारिक आन्दोलन है।

1990 के वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अप्रभावित नहीं रहा। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में नयी-नयी संकल्पनाओं जैसे मुक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, सेमेस्टर प्रणाली, ट्राइमेस्टर प्रणाली, कम्प्यूटर आधारित शिक्षा, शिक्षक छात्र सम्बन्ध, वर्चुअल क्लास रूम आदि का चलन बढ़ा है। ऐसे में इन परिवर्तनों के बीच अभावपि अपने को Most Updated and Relevant Organization बनाने के लिए सतत चिंतनशील रहती है। अभावपि द्वारा अपने कार्य को गतिमान बनाने हेतु महाविद्यालय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इकाई का गठन किया जाता है। यही इकाइयां अभावपि के कार्य की आधार स्तम्भ होती हैं।

अभावपि का समाज में प्रस्तुतीकरण इन्हीं इकाइयों के माध्यम से होता है। अतः अभावपि की इकाई आकर्षक, प्रभावी तथा गतिमान होनी चाहिए। इकाई को आकर्षक, प्रभावी तथा गतिमान बनाने हेतु प्रत्येक कार्यकर्ता को

नमोन्मेषी होना होगा।

हाल के दिनों में माइक्रोसाफ्ट कम्पनी के सीईओ सत्या नडेला द्वारा लिखित पुस्तक 'Hit Refresh' काफी चर्चा में रही। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि 'The Quest to Rediscover Microsoft soul and imagine a better Future for Every One' काफी चर्चा में रही। इसमें उन्होंने लिखा है कि किसी भी संस्था/संगठन को अपने आत्मा का अन्वेषण करते रहना चाहिए और उसे प्रत्येक व्यक्ति के सुन्दर भविष्य के लिए कार्य करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने परिवर्तन के प्रति सचेष्ट रहते हुए सतत प्रयोगधर्मी बनने हेतु आग्रह किया है। रिफ्रेश बटन के प्रयोग पर बल दिया है। अभावपि को भी हर स्तर पर बदलाव के लिए प्रयास करना चाहिए। सत्या नडेला के इस उद्धरण का प्रयोग अभावपि में करते हुए अपने Vision Mission एवं Action के बारे में पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

आज दुनिया की प्रायः सभी बड़ी कंपनियों के सीईओ औसतन 25-40 वर्षों के बीच हैं। उनके नेतृत्व में ये कम्पनियां सफलता के साथ आगे भी बढ़ रही हैं। इसके पीछे बड़ा कारण उनके युवा नेतृत्व को जाता है। युवा प्रयोगधर्मी होता है। परिवर्तन के प्रति उसके अन्दर एक नया उत्साह और विश्वास होता है।

अभावपि छात्रों और युवाओं का संगठन है। इसीलिए परिवर्तन के प्रति हमें आग्रही होना चाहिए। परिवर्तन के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण के कारण ही आज आयोजित

दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में कार्यरत है। मार्क्स बहुत बड़ा चिन्तक था, लेकिन उसका विचार एक परिस्थिति के विरोध में उभर कर आया हुआ विचार था, परन्तु हमारी विचारधारा किसी विरोध की उपज नहीं है। हमारी विचारधारा Time tested है, क्योंकि यह भारत की सनातन संस्कृति को सम्पोषित करने वाले उदात्त जीवन मूल्यों से अनुप्राणित है। हम स्वामी विवेकानंद, अरविन्द घोष, हेडगेवार जी, गुरु जी, डा0 अम्बेडकर जी के जीवन आदर्शों से अभिप्रेरित कार्यकर्ता हैं, जो हर परिवर्तन के प्रति एक रचनात्मक दृष्टि के साथ कार्य करने हेतु संकल्पित हैं। अतः हमें अपनेल विचारधारा को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करना चाहिए।

हमारी कार्य पद्धति, हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

यह भी Time tested है। प्रा. यशवंत राव केलकर जी के कार्य व्यवहार से अपनी कार्य पद्धति को आसानी से समझा जा सकता है। अभावपि के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए वह प्रेरणास्पद है। उन्होंने एक किताब लिखी है - 'Towards Man Making'. इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर श्री संपत जी भी उपस्थित थे, वे एक बड़े प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि 'I am missing in my life'. प्रा. यशवंत राव केलकर जी से उनको प्रत्यक्ष मिलने का

अवसर नहीं प्राप्त हो सका था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। विद्यार्थी परिषद् की कार्यपद्धति के कारण ही समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्य करते हुए उसके कार्यकर्ता आज उस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाये हुए हैं। विद्यार्थी परिषद् की कार्यपद्धति को अपनाकर यदि गणित का विद्यार्थी उद्योग के क्षेत्र में श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचता है, तो इसके पीछे मूल ताकत हमारी कार्यपद्धति है। इसीलिए हमारी कार्यपद्धति को प्रबंधन की श्रेष्ठतम पद्धति के रूप में आज जन सामान्य की स्वीकृति प्राप्त हो रही है। 1985 में अभावपि ने World Organization of Student and Youth (WOSY) के नाम से एक प्रकल्प प्रारंभ

किया। हैदराबाद में WOSY का सम्मेलन था, जिसमें 72 देशों के युवा प्रतिभाग किये थे। सामान्यतया इस तरह के आयोजनों को मौजमस्ती के रूप में देखा जाता है। परन्तु इस आयोजन में अफगानिस्तान से प्रतिभाग करने वाले एक छात्र ने, जो कहा उसे उद्धृत करना यहां अत्यधिक सार्थक होगा। उसने कहा कि WOSY के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से अफगानिस्तान के विकास की भी दिशा कैसी हो? इसकी दृष्टि विकसित हुई है। अभावपि की रचनात्मक दृष्टि का ही परिणाम है कि Global Terrorism जैसे संवेदनशील विषय पर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युवा समाधान के विकल्पों पर परस्पर सहयोग व सामंजस्य के साथ विचार विमर्श करते हैं।

मार्क्स बहुत बड़ा चिन्तक था, लेकिन उसका विचार एक परिस्थिति के विरोध में उभर कर आया हुआ विचार था, परन्तु हमारी विचारधारा किसी विरोध की उपज नहीं है। हमारी विचारधारा Time tested है, क्योंकि यह भारत की सनातन संस्कृति को सम्पोषित करने वाले उदात्त जीवन मूल्यों से अनुप्राणित है। हम स्वामी विवेकानंद, अरविन्द घोष, हेडगेवार जी, गुरु जी, डा0 अम्बेडकर जी के जीवन आदर्शों से अभिप्रेरित कार्यकर्ता हैं, जो हर परिवर्तन के प्रति एक रचनात्मक दृष्टि के साथ कार्य करने हेतु संकल्पित हैं।

वैश्वीकरण के दौर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बदलाव की ओर हम अग्रसर हुये हैं। Technological Advancement के कारण आज हम Artificial Intelligence, Vertual University, Driverless Car आदि की बात कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। Driverless कार के चलन से दुर्घटनाओं में 40 प्रतिशत तक की कमी की सम्भावना है। इन परिवर्तनों का देश और समाजहित में प्रयोग अभावपि

के कार्यकर्ता बड़े ही दक्षता एवं आत्मविश्वास पूर्वक आज कर रहे हैं।

गूगल के कारण सूचना के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है। पहले जिन सूचनाओं को प्राप्त करने में महीनों लगते थे, अब गूगल के माध्यम से कुछ सेकेण्ड में हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है उससे हमारी पहुंच बढ़ी है। सोशल मीडिया के माध्यम से विचारों के प्रेषण की शक्ति आज कई गुणा बढ़ गई है। आज सामाजिक समस्याओं से लड़ने तथा समाधान प्राप्त करने की दिशा में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गयी है। टेक्नोलॉजी के कारण घटनाओं को देखने, समझने तथा

उस पर प्रतिक्रिया करने के स्वरूप में बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के कारण देश के विकास की दिशा में अपने रचनात्मक भूमिका को लेकर युवा जागरूक हुआ है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग में सावधानी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हम उसके दास नहीं बल्कि मालिक हैं।

कार्य का अत्यधिक दबाव होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति आज अत्यंत ही व्यस्त है। व्यस्तताओं के बीच सामाजिक कार्यों के लिए समय निकालना एक चुनौती है। अपने प्रभाव व दक्षता को बढ़ाने हेतु दुनिया की 90 प्रतिशत कम्पनियां अपने कार्य को Redesign करने का प्रयास कर रही हैं। अभावपि को भी अपने कार्य का Redesign करने की आवश्यकता है। आज देश का युवा अभावपि से जुड़ना चाहता है क्योंकि भारत के पुनर्निर्माण की समुचित दृष्टि और व्यापक योजना उसके पास है। इसीलिए अपनी व्यस्तताओं के बीच देश का आम छात्र अभावपि के लिए कार्य करना चाहता है। अभावपि में काम करने के लिए लोगों के पास समय भी है और मन भी है। अतः लोगों के रुचि, आवश्यकता व उपलब्धता के आधार पर उसके कार्य की योजना बनाना महत्वपूर्ण है।

अभावपि के कार्य को आकर्षक बनाने हेतु सीमित कार्यकर्ताओं के समूह से हमें बाहर आना चाहिए। इसके लिए हमें Top to Bottom की बजाय Bottom to Top के approach को अपनाना होगा। सभी प्रकार के लोगों तक हमारी पहुँच बढ़े, इस हेतु कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ानी होगी। सभी प्रकार के छात्रों को अपने कार्य से जोड़ना होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर एक ही इकाई काम करें, इससे अच्छा है कि संकायवार/विभागवार इकाई का गठन कर अपने कार्य की प्रक्रिया में अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ा जाय। NCC, NSS के छात्रों की टीम बनाकर नेतृत्व में गुणों का विकास करना, जिससे परिसर से लेकर समाज जीवन में नेतृत्वकर्ता की

भूमिका में छात्र आगे आयें। We should become a leader of leaders आज शिक्षालयों में पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से छात्र अंकों की अंधी दौड़ में शामिल है, जिन्हें यह नहीं पता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? अर्थात् शिक्षालय के पाठ्यक्रम छात्रों में जीवन दृष्टि विकसित करने में असफल दिखायी दे रहे हैं। ऐसे समय में छात्रों के अन्दर जीवन दृष्टि विकसित करने हेतु अनुभव आधारित कार्यक्रमों के संचालन की आवश्यकता होती है। अभावपि ने छात्रों में देशभक्ति के भाव जागृत करने तथा समाज के प्रति संवेदन विकसित करने हेतु सामाजिक अनुभूति का कार्यक्रम चलाया है।

जिसके अच्छे अनुभव सामने आ रहे हैं। इसलिए शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए... यह हमारे लिए केवल नारा नहीं बल्कि यह हमारी प्रतिबद्धता है।

सूचना क्रांति के परिणामस्वरूप सोशल मीडिया की भूमिका अभिमत निर्माण में काफी महत्वपूर्ण हो गयी है। फेसबुक के माध्यम से हम बड़े पैमाने पर एक दूसरे से जुड़कर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। विचार विनियम का, फेसबुक आज एक सशक्त मंच बन चुका है। Connect & Share के माध्यम से फेसबुक दुनिया के युवाओं को जोड़ने

को कार्य कर रहा है। अभावपि को फेसबुक की ही भाँति या इससे आगे बढ़कर Connect, Share & Act के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में युवाओं की भूमिका को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास करना होगा। अभावपि के कार्य को प्रभावी बनाने हेतु Purpose, Passion & Platform तीनों की आवश्यकता होती है। अपने कार्य के विस्तार के लिए फेसबुक को एक प्रभावी प्लेटफार्म के रूप में आगे उपयोग में लाने की आवश्यकता है।

सामूहिकता हमारे कार्यपद्धति का मुख्य विचार है। सामूहिकता हमारे व्यवहार में दिखायी देनी चाहिए। आज अपने काम में तीन प्रकार के लोग हैं - Few People are giving full time, some people

आज ऐसे छात्र बड़ी संख्या में हैं जो महाविद्यालय परिसर में तो नहीं जाते, लेकिन कोचिंग क्लासेज तथा मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं ऐसे बहुत से महाविद्यालय हैं, जहां विद्यार्थी परिषद् की सदस्यता नहीं होती है। कोई कार्यक्रम नहीं होता है। ऐसे महाविद्यालय को विव्रित कर वहां पहुंचना, 'सेल्फी विथ कैम्पस/कॉलेज' अभियान को चलाकर उस महाविद्यालय तक पहुंचने का प्रयास करना। ऐसा करते हुए धीरे-धीरे वहां अपने कार्य को प्रारम्भ करना, जिससे जो महाविद्यालय(कॉलेज) अभी हमारी पहुंच से बाहर हैं वहां हम अपनी पहुंच बना सकें।

are giving more time and more people are giving less time. इन तीनों प्रकार के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए सबकी सहभागिता के साथ कार्य को आगे ले जाना, यह हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। जहां 10 या 20 कार्यकर्ता मिलकर निर्णय लेते थे। वहां निर्णय की प्रक्रिया में अधिक लोगों को सहभागी बनाना, जिससे कार्य में सहभागिता तथा उसकी स्वीकार्यता अधिक से अधिक बढ़ सके।

अपने कार्य के विस्तार और उसके प्रभाव की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हम वहां पहुंचें, जहां अब तक नहीं पहुंच पाये हैं। अभावपि के कार्य का विस्तार उन स्थानों पर आसानी से हो सकता है, जहां भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोषणा करने वाले लोग हैं।

जिन स्थानों पर महाविद्यालय परिसर नहीं है, लेकिन वहां कोचिंग क्लासेज चलती हैं, वहां भी अभावपि को पहुंचना चाहिए और वहां के छात्रों के बीच अपना कार्य प्रारम्भ करना चाहिए। ओपेन यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को अपने कार्य से जोड़ना तथा अभावपि के कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज ऐसे छात्र बड़ी संख्या में हैं जो महाविद्यालय परिसर में तो नहीं जाते, लेकिन कोचिंग

क्लासेज तथा मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं ऐसे बहुत से महाविद्यालय हैं, जहां विद्यार्थी परिषद् की सदस्यता नहीं होती है। कोई कार्यक्रम नहीं होता है। ऐसे महाविद्यालय को चिन्हित कर वहां पहुंचना, 'सेल्फी विथ कैंपस/कॉलेज' अभियान को चलाकर उस महाविद्यालय तक पहुंचने का प्रयास करना। ऐसा करते हुए धीरे-धीरे वहां अपने कार्य को प्रारम्भ करना, जिससे जो महाविद्यालय(कॉलेज) अभी हमारी पहुंच से बाहर हैं वहां हम अपनी पहुंच बना सके।

अभावपि के पूर्व कार्यकर्ता उसकी बहुत बड़ी ताकत है। उसके पूर्व कार्यकर्ता आज समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। उनके साथ सम्पर्क, संवाद और सहयोग के माध्यम से अपने

कार्य को गति देने में विशेष मदद मिल सकती है। नये कार्यकर्ताओं से बात करने की जिम्मेदारी पूर्व कार्यकर्ता को दे सकते हैं। कार्यक्रम में स्वागत समिति, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अपने कार्य में पूर्व कार्यकर्ताओं से सहयोग प्राप्त करने हेतु अपने पास उनका एक डेटा बैंक होना चाहिए। इस काम में हम टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं।

देश और दुनिया में हो रहे बदलावों को अभावपि के कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए। इन बदलावों को ग्रहण करने का मन होना चाहिए। देश और दुनिया में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार अभावपि को अपनी छवि बदलनी चाहिए। अभावपि के बारे में लोगों की कल्पना है कि

अभावपि के बारे में लोगों की कल्पना है कि यह एक आंदोलन करने वाला संगठन है, देश और समाज के लिए काम करने वाला संगठन है, छात्रों में राष्ट्र के भाव जागृत करने वाला संगठन है, समाज के प्रति संवेदना विकसित करने वाला संगठन है। विद्यार्थियों के अन्दर रचनात्मक को बढ़ाने वाला संगठन है। विद्यार्थी परिषद् को समग्रता के साथ प्रस्तुत करने हेतु सभी प्रकार के गतिविधियों के लिए कार्यकर्ता की टीम तैयारी करने की आवश्यकता है।

यह एक आंदोलन करने वाला संगठन है, देश और समाज के लिए काम करने वाला संगठन है, छात्रों में राष्ट्र के भाव जागृत करने वाला संगठन है, समाज के प्रति संवेदना विकसित करने वाला संगठन है। विद्यार्थियों के अन्दर रचनात्मक को बढ़ाने वाला संगठन है। विद्यार्थी परिषद् को समग्रता के साथ प्रस्तुत करने हेतु सभी प्रकार के गतिविधियों के लिए कार्यकर्ता की टीम तैयारी करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण, शहरी, आदिवासी, जनजाति, पिछड़ी सभी प्रकार के विद्यार्थियों को अपने कार्य के साथ जोड़ने के लिए हमें अपने कार्य को बहुआयामी बनाना होगा, हमने ऐसा किया भी है। अभावपि को बदलते परिदृश्य में एक "कास्मोपोलिटन आर्गेनाइजेशन" बनाने का प्रयास होना चाहिए। नये विचारों का स्वागत होना चाहिये तथा उसे लागू करने का प्रयास करना चाहिए। हमें तर्क और चिंतन की प्रक्रिया को अपने कार्य में महत्व देते हुए अपने को सदैव Refresh, Re-energize, Renew, Reframe तथा Rethink करते रहना चाहिए, तभी हम अपने महान उद्देश्य "राष्ट्रीय पुनर्निर्माण" के लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। ■

(लेखक अभावपि के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री हैं।)

‘सेल्फी विद कैंपस’ के माध्यम से डेढ़ लाख परिसर तक पहुंचेगी अभाविप

31 खिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) के द्वारा देश भर में ‘सेल्फी विद कैंपस’ अभियान चलाये जाने की योजना है, यह अभियान 30 जुलाई से पांच अगस्त तक देश भर के विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं 10+2 विद्यालयों में चलाई जायेगी। बता दें कि ‘सेल्फी विद कैंपस’ की संकल्पना रांची में संपन्न अभाविप के 63 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री के. एन. रघुनंदन ने कार्यकर्ताओं को नई दृष्टि – नया स्वरूप अपनाकर परिषद् के कार्यक्रमों में नये – नये प्रयोग करने की बात कही थी, उसमें एक प्रयोग ‘सेल्फी विद कैंपस’ भी था।

के. एन. रघुनंदन के मुताबिक विद्यार्थी परिषद्, कार्य एवं कार्यक्रमों की प्रकृति नित्य नूतन विचार साधन, व्यक्तियों को साथ लेकर अपने मूल सिद्धांतों की मर्यादा के साथ आगे बढ़ने की रही है, आज विद्यार्थी परिषद् देश दुनिया में एक जिम्मेदार, सक्रिय, जागरूक छात्र संगठन की भूमिका निभा रही है। देश भर के परिसरों में संख्यात्मक, प्रतिनिधित्व और विस्तार की दृष्टि से सक्रियता का अन्य किसी छात्रसंगठनों से कोई मुकाबला नहीं है। किन्तु प्रथम स्थान पर होने के बावजूद देश भर के सभी शैक्षिक परिसरों में अभाविप नहीं पहुंच पायी है। सरकारी जानकारी के मुताबिक आज देश भर में लगभग एक लाख 65 हजार विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा + 2 विद्यालय हैं। लेकिन परिषद् की सक्रियता, संपर्क, इकाई अधिकतम 10 प्रतिशत परिसरों तक हो पाती है। इस बड़े अंतराल को पाटने के लिए इस वर्ष अभाविप के द्वारा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र को अपने संपर्क में लेने का एक महाअभियान आज के छात्रों – युवाओं की रूचि, अभिरूचि को ध्यान में रख कर एक आकर्षक अभियान की योजना की है “सेल्फी विद कैंपस” अभियान आज

के छात्रों की रूचि को ध्यान में रखकर लक्ष्य प्राप्ति की ओर एक कदम है, जिसके माध्यम से देश भर में फैले परिषद् के हजारों कार्यकर्ता देश के सभी एक लाख पैसठ हजार परिसरों में संपर्क करेंगे।

‘सेल्फी विद कैंपस’ अभियान के अंतर्गत देश भर में परिषद् कार्य का संगठनात्मक विस्तार हेतु व्यापक योजना बनाई है। इस विशेष योजना के अंतर्गत जुलाई माह में अभियान की पूर्ण योजना के अंतर्गत देश भर के कार्यकर्ताओं को सीधे महाविद्यालयों के साथ जोड़ने का कार्य की जायेगी। देश भर में पचास हजार सक्रिय कार्यकर्ताओं को इन एक लाख पैसठ हजार परिसरों में पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है, अभियान को सफल बनाने के लिए अभाविप के द्वारा देश भर में कार्यशाला आयोजित हो रही है। कार्यशाला में यह बताया गया कि जिला, तहसील तथा संस्थान की कार्यायोजना के माध्यम से छात्र इस अभियान में शामिल होंगे। 30 जुलाई से 5 अगस्त तक चलने वाले अभियान में परिषद् के कार्यकर्ता अपने लिए निर्धारित परिसरों में जाकर वहां के छात्रों, प्रशासनों

‘सेल्फी विद कैंपस’ अभियान के अंतर्गत देश भर में परिषद् कार्य का संगठनात्मक विस्तार हेतु व्यापक योजना बनाई है। इस विशेष योजना के अंतर्गत जुलाई माह में अभियान की पूर्ण योजना के अंतर्गत देश भर के कार्यकर्ताओं को सीधे महाविद्यालयों के साथ जोड़ने का कार्य की जायेगी।

शिक्षकों से संपर्क करेंगे। छात्रों के साथ परिसरों में सेल्फी लेंगे, साथ ही इस अभियान के लिए बनाये गये विशेष एप में छात्रों के संपर्क के साथ फोटो अपलोड करेंगे। इस अभियान में इस ‘एप’ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस एप में फोटो सहित जानकारी अपलोड होने के बाद ही इसे पूर्ण माना जायेगा। इस अभियान के माध्यम से देश भर के 1.65 लाख परिसरों में परिषद् का संपर्क होगा, उनके साथ संवाद बढ़ेगा। आने वाले समय में परिषद् की सदस्यता भी इन नये संपर्कित संस्थानों में होगी। अगले माह में इन सभी संस्थानों में परिषद् संपर्क समिति बनाई जायेगी। कार्य विस्तार के उद्देश्य को लेकर बनाये गये। अभाविप का मानना है कि इस अभियान से परिषद् की पहुंच/संपर्क सर्वव्यापी तथा सर्वस्पर्शी होगी। ■

ABVP NEC Meeting 28th to 30th May, Guwahati (Assam)

Make Education System Transparent and Qualitative

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad is deeply concerned by the recent leaks of question papers and mismanagement in conduction of examinations at various places in the country. Lakhs of students had to face inconvenience & mental agony because of the leak of question papers, in renowned institution such as SSC and CBSE recently. Everyone saw the recent failure in the conduct of CLAT exam at various centers all over the country. Thousands of students were badly affected because of this, which is indeed a worrying issue. The immediate response to the petition filed in Delhi court by ABVP from the students shows that this exam needs to be conducted again.

ABVP demands that central government should address the issues concerning conduct of exam and should check paper leaks and frame policies to prevent failures in future. ABVP believes that exemplary punishment should be given to those accused in question paper leak cases. This Executive Council also proposes setting up of a National Exam Conducting Board as a long term and far reaching solution to these issues.

University exams and national level entrance exams are being converted into online mode without proper infrastructural support and planning. Although ABVP supports online conduct of exams, we demand that it should be backed by proper timing wherein necessary support can be arranged for conduct of exam. This National Executive Council of ABVP demands that as many students till now are not properly acquainted with computers, exams should be conducted in both online & offline mode in the initial years. Also, it is a considerate thought of ABVP that educational institutions should conduct mock tests for online examinations.

This NEC of ABVP demands that all state governments and central government should work proactively to promote sports in universities by establishing Faculty of Sports in the Universities. Adequate support should be provided to the students who want to choose

sports as a career option.

ABVP National Executive Council welcomes the step taken by UGC to give 70% weightage to the written test and 30% to interview for entrance exams of Ph.D. or M.Phil. as this will bring transparency into the system.

The National Education Policy has been debated and discussed many a times during last three years. It is alarming that the draft has not been released yet. It is the firm belief of ABVP that the draft of National Education Policy should be brought at the earliest and attention should be paid to its implementation. This National Executive Council reiterates its demand for immediate declaration of National Education Policy incorporating the suggestions put forth by ABVP therein.

Many vacant posts of teachers in majority of universities in the country is impacting the quality of education. For ensuring qualitative education, ABVP has, time and again, raised demand for appointment of teachers. This National Executive Council reiterates its demand to fill up all the vacant posts of teachers by the government immediately. ABVP also demands appointment against SC/ST/OBC/PWD (Divyang) posts without delay and further demands to ensure proper arrangements in place for teachers.

ABVP believes that level of education imparted in government schools should be improved. The steps taken by some state governments to rejuvenate government schools deserve admiration. ABVP NEC demands that decision about school education should be taken in student's interest.

The growing privatization of education is a serious concern. It is a well thought of opinion of ABVP that academic autonomy should be given to education institutions of excellence. But to allow commercialization in the name of autonomy is a serious concern. In this regard, this National Executive Council demands that Central Government should rethink the decision of granting financial autonomy to universities. ■

उच्च शिक्षा का बेहतर विकल्प है दूरस्थ माध्यम

देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक और परा-स्नातक स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन, ऐसे छात्रों की संख्या काफी अधिक है, जिन्हें विभिन्न कारणों की वजह से किसी विश्वविद्यालय में अभी तक प्रवेश नहीं मिल पाया है। ऐसे छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके लिए दूरस्थ या मुक्त शिक्षा के द्वार अभी भी खुले हुए हैं। उच्च शिक्षा की बात करें तो दूरस्थ शिक्षा के जरिये आज स्नातक और परा-स्नातक से लेकर डिप्लोमा, सर्टीफिकेट और एमफिल तथा पीएचडी जैसे पाठ्यक्रम भी किए जा सकते हैं।



। उमाशंकर मिश्र ।

क म अंकों की वजह से किसी नियमित संस्थान में आपको प्रवेश नहीं मिल पाया है, उच्चतर शिक्षा संस्थान आपकी पहुंच से दूर है या फिर आप देर से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई में अंतराल आ गया हो, फीस वहन करना कठिन हो या फिर आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आप नौकरी करने के साथ-साथ पढ़ाई भी जारी रखना चाहते

हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूरस्थ शिक्षा के द्वार ऐसे शिक्षार्थियों के लिए हमेशा खुले रहते हैं।

दूरस्थ शिक्षा भारत में उच्च शिक्षा स्पेक्ट्रम का प्रमुख हिस्सा है। दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो पत्राचार या ऑनलाइन मोड पर आधारित होती है। शिक्षा की इस प्रणाली में अन्य शिक्षण संस्थानों की तरह छात्रों को नियमित उपस्थिति दर्ज कराने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह की शिक्षा पद्धति में न केवल प्रवेश, बल्कि शिक्षण की प्रक्रिया से जुड़े नियम काफी शिथिल होते हैं,

जिसका प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है। मूल रूप से दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी पद्धति है, जिसके माध्यम से छात्रों को सप्ताहांत कक्षाएं, इंटरनेट, वीडियो, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो / ऑडियो टेप आदि जैसे विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाता है।

अधिकतर मामलों में मुक्त या दूरस्थ शिक्षा संस्थानों द्वारा पाठ्य सामग्री और पाठ्यक्रम डाक से भेज दिया जाता है, जिसकी मदद से आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। छात्र संस्थान से संबद्ध अपने नजदीकी अध्ययन केंद्रों में कक्षाएं भी ले सकते हैं और समस्याओं के बारे में शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। सत्र के अंत में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसके बारे में छात्रों को संस्थान की वेबसाइट या फिर पत्राचार के जरिये जानकारी मुहैया करायी जाती है। परीक्षा परिणाम के बारे में जानकारी भी इसी तरह से मिल सकती है। किसी तरह की जिज्ञासा और पूछताछ के लिए संबंधित संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों के दिए गए नंबरों पर बातचीत भी की जा सकती है।

दूरस्थ शिक्षा को ऐसे लोग भी अपना पसंद करते हैं, जो शैक्षिक योग्यता बढ़ाकर आप अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल मजबूत करना चाहते हैं। ये पाठ्यक्रम करके वे वेतन में बढ़ोत्तरी या प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है, जो किसी कारणवश स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद आगे पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा किसी वरदान से कम नहीं है।

दूरस्थ शिक्षा की वैधता, प्रामाणिकता और स्वीकार्यता की चिंता के कारण बहुत-से छात्र इसे अपनाने से कतराते हैं। मगर, ऐसा सोचना गलत है क्योंकि किसी शैक्षिक पाठ्यक्रम से संबंधित इंडस्ट्री में कुछेक अपवादों को छोड़कर दूरस्थ शिक्षा की स्वीकार्यता और उसकी मान्यता नियमित शिक्षा संस्थानों से मिलने वाली डिग्री से अलग नहीं होती है। हालांकि, दूरस्थ शिक्षा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कई फर्जी संस्थान भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसलिए संस्थानों का चयन करते वक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दूरस्थ शिक्षा में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वैधानिक निकायों द्वारा संबंधित संस्थान को मान्यता प्राप्त हो, विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा परिषद (Distance Education Council), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, अध्यापन तथा

शिक्षण के तौर-तरीकों तथा समय-निर्धारण के साथ-साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश मानदंडों के संबंध में भी उदार है। देश की मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने वाले प्रमुख संस्थानों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), राज्यों में स्थित मुक्त विश्वविद्यालय (एसओयू) और परंपरागत विश्व विद्यालयों के पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा विभाग शामिल हैं। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विनियामक अधिकार इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में निहित हैं।

भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1956-1960 के अपनी रिपोर्ट में सायंकालीन महाविद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रम आदि शुरू करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद भारत में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। वर्ष 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय शुरू हुआ और 1970 के दशक में पत्राचार पाठ्यक्रमों का विकास एवं प्रसार हुआ। वर्ष 1980 के दशक में सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली की शुरुआत की। वर्ष 1982 में सर्वप्रथम हैदराबाद स्थित डॉ भीमराव आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद वर्ष 1985 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। इग्नू विज्ञान सहित सभी विषयों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है और इसके केंद्र देशभर में हैं। वर्ष 1987 में कई राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय खुले। इसके बाद नवम्बर, 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। वर्ष 1991 में इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) की स्थापना की गई और फिर जून, 2013 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई।

दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं

दूरस्थ शिक्षा में सभी पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाओं की संख्या तय होती है और देश भर के कई केंद्रों पर उनकी पढ़ाई होती है। सूचना क्रांति और इंटरनेट के कारण दूरस्थ शिक्षा और आसान एवं प्रासंगिक हो गयी है। विजुअल क्लासरूम लर्निंग, इंटरैक्टिव ऑनसाइट लर्निंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विद्यार्थी देश के किसी

भी राज्य में रहकर घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। इस शिक्षा प्रणाली को अपनाकर विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पढ़ने की समय-तालिका बना सकते हैं। कम खर्चीली होने के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई करने की शुल्क (फीस) काफी कम है। इसमें सीटों की सीमित संख्या की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है और नौकरी करने के साथ-साथ पढ़ाई की जा सकती है। एक अच्छी बात यह है कि कम अंक आने पर भी मनपसंद पाठ्यक्रम में दाखिला मिल जाता है और किसी भी पाठ्यक्रम के लिए उम्र बाधा नहीं होती है। दूरस्थ शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य 'पाठ्य सामग्री तैयार करना' है। इसमें शिक्षक सामने नहीं होते। इसलिए पाठ्य सामग्री ही शिक्षक का काम करती है। साधारण पाठ्यक्रम के साथ ही वोकेशनल पाठ्यक्रम तथा प्रोफेशनल पाठ्यक्रम भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किये जा सकते हैं। पत्राचार से किए गए कोर्सों की मान्यता कहीं कम नहीं आंकी जाती। ये भी नियमित पाठ्यक्रम की तरह ही महत्वपूर्ण होते हैं।

हर तरह के पाठ्यक्रम(कोर्स) उपलब्ध

आज कल दूरस्थ शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी स्नातक (ग्रेजुएट), एमफिल, पीएचडी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आदि सभी पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इसमें छात्रों को बीए, बीकॉम जैसे पाठ्यक्रम कराने का कारगर माध्यम है। आर्ट्स और सोशल साइंस में प्रतिष्ठा (ऑनर्स) पाठ्यक्रम करने के विकल्प दूरस्थ शिक्षा में उपलब्ध हैं। इग्नू में आर्ट्स और कॉमर्स के अलावा साइंस और मैनेजमेंट के भी पाठ्यक्रम बखूबी चलाए जा रहे हैं। यहां स्नातक समान्य (बीए जनरल) पाठ्यक्रम के साथ ही बीएससी जनरल की पढ़ाई भी होती है, जिसमें छात्रों को गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान (बॉटनी) एंड प्राणिविज्ञान (जूलॉजी) जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा बीबीए इन रिटेलिंग, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जैसे पाठ्यक्रम हैं। इसके अलावा व्यवसायिक प्रशिक्षण (वोकेशनल ट्रेनिंग) के रूप में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी हैं। यहां बीएड और डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी डीएड पाठ्यक्रम भी अब दूरस्थ शिक्षा में शामिल हो गया है। इसके अलावा अनुवाद में डिप्लोमा, डिग्री, बी-लिब और एम-लिब का पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। एमए स्तर पर जेंडर स्टडीज, अनुवाद,

समाजशास्त्र और शिक्षा में एमए जैसे पाठ्यक्रम भी लीक से हट कर चल रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के तहत बीए, बीकॉम के साथ ही बीकॉम ऑनर्स का पाठ्यक्रम भी है। यहां अंग्रेजी और राजनीतिशास्त्र ऑनर्स की भी पढ़ाई होती है। बीए प्रोग्राम में कई वोकेशनल विषय भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे द्वितीय वर्ष में फाउंडेशन पाठ्यक्रम के तहत छात्रों को तीन पेपर दिए गए हैं। पहला समकालीन भारत, दूसरा मानवाधिकार, जेंडर और पर्यावरण है और तीसरा भाषा, साहित्य और संस्कृति। तीसरे वर्ष में यहां एप्लिकेशन पाठ्यक्रम के तहत बेसिक स्टेटिस्टिक्स, ग्लोबलाइजेशन, मैथमैटिक्स फॉर सोशल साइंस और वालेंटरी ऑर्गनाइजेशन का पेपर है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पत्राचार माध्यम के रूप में आर्ट्स और कॉमर्स के अलावा बैचलर इन इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इश्योरेंस जैसे पाठ्यक्रम हैं। यहां डिस्टेंस एजुकेशन के तहत डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन पावर जनरेशन, जियोइंफॉर्मेटिक्स और गाइडेंस एंड काउंसिलिंग का पाठ्यक्रम है।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने भी दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस लर्निंग) में कई अनूठे पाठ्यक्रम चलाए हैं। इनमें जनरल आर्ट्स और कॉमर्स के अलावा गणित और भूगोल में एमएससी और एमए कराया जाता है। छात्रों को बैचलर इन इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट और एलएलएम जैसे पाठ्यक्रम खूब लोकप्रिय हैं। एमसीए, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जैसे पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

वर्धा स्थित महात्मा गांधी हिन्दी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय देशभर में छात्रों के लिए बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पाठ्यक्रम चला रहा है। यहां बीबीए के अलावा एमबीए भी हिन्दी माध्यम में उपलब्ध है। यहां छात्रों के लिए बीलिब, एम-लिब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन व फिल्म प्रोडक्शन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इनके अलावा गुरु जंभेश्वर, हिमाचल विश्वविद्यालय, एमडीयू रोहतक, पंजाब टेक्निकल विश्वविद्यालय, अन्नामलाई और पांडिचेरी जैसे कई विश्वविद्यालय भी अपने यहां तरह-तरह के पाठ्यक्रम डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से चला रहे हैं।

दाखिले के लिए कोई बाध्यता नहीं

दूरस्थ शिक्षा माध्यम से दाखिला लेने में आमतौर पर अंकों और मेधा (मेरिट) जैसी बाधाएं सामने नहीं आती हैं। यहां दाखिले के लिए पर्याप्त समय भी छात्रों मिलता है। विलम्ब शुल्क के साथ ज्यादातर विश्वविद्यालयों में दाखिले अक्टूबर और नवम्बर तक चलते हैं। विज्ञान के अलावा एमबीए और बीएड जैसे कई प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में दाखिला प्रवेश परीक्षा के जरिये दिया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां सितम्बर तक दाखिले का मौका देता है, वहीं इग्नू और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय समेत कई संस्थान साल में दो बार दाखिले की प्रक्रिया संचालित हैं। इन संस्थानों में आमतौर पर पहला सत्र जुलाई में और दूसरा सत्र जनवरी में शुरू होता है। छात्र अपनी जरूरत एवं रुचि के अनुसार इनमें प्रवेश ले सकते हैं।

कुछ प्रमुख दूरस्थ शिक्षा केन्द्र

- ▶ इग्नू, मैदानगढ़ी, दिल्ली
- ▶ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
- ▶ दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

- ▶ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली
- ▶ अन्नामलाई विश्वविद्यालय
- ▶ पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
- ▶ हिमाचल विश्वविद्यालय, शिमला
- ▶ गुरु जंभेश्वर, हिसार, हरियाणा
- ▶ एमडीयू, रोहतक, हरियाणा
- ▶ पंजाब टेक्निकल विश्वविद्यालय
- ▶ सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय
- ▶ महात्मा गांधी हिन्दी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय

राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (एसओयू)

देश भर में फिलहाल 13 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हैं, जो एकल मोड संस्थाएं हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल दूरस्थ मोड में शिक्षा प्रदान करते हैं। ये विश्वविद्यालय उन लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, जो विभिन्न कारणों से नियमित पाठ्यक्रमों में शिक्षा नहीं ले पाते हैं। ये विश्वविद्यालय पहले से ही कार्यरत शिक्षार्थियों के करियर के विकास को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

क्र. सं.	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	पता	संपर्क सूत्र	वेबसाइट
1.	डा. बी. आर. आम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (बीआरएओयू), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-(1982)	प्रो. जी.राम रेड्डी मार्ग रोड नं. 46, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033	Tel: 91-40-23544910 Fax: 91-40-23544830	https://braou.ac.in/
2.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय (वीएमओयू), कोटा, राजस्थान-(1987)	रावतभाटा रोड, अखेलगढ़, कोटा, राजस्थान	Tel: 91-744-2471254 Fax: 91-744-2470451	http://www.vmou.ac.in/
3.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना, बिहार-(1987)	तीसरा तल, बिस्कोमान भवन, वेस्ट गांधी मैदान, पटना-800001, बिहार	Tel: 91-612-2201013 Fax: 0612 2201001	http://www.nalandaopenuniversity.com/
4.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय (वायसीएमओयू), नासिक, महाराष्ट्र-(1989)	दनयानागंगोत्री, गंगापुर बांध के पास, नासिक-422222, महाराष्ट्र	Tel: 91-253-2231714, 2231715 Fax: 91-253-2231716	https://www.ycmou.ac.in/

5.	मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय (एमपीबीओयू), भोपाल, मध्य प्रदेश- (1991)	आईटीआई (गैस राहत), बिल्डिंग गोविंदपुरा, भोपाल- 462023	Tel: 0755 2784102, 5272017 Fax: 91-755-2600704	http://www. bhojvir tualuniversity. com
6.	डा. बाबासाहेब आम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (बीएओयू), अहमदाबाद, गुजरात- (1994)	सरकारी बंगला नं.9, दफनाला, शाही बाग, अहमदाबाद-380003, गुजरात	Tel: 91-79-22869690/91 Fax: 91-79-22869691	http://baou.edu. in/
7.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (केएसओयू), मैसूर, कर्नाटक- (1996)	मनसांगंगोत्री, मैसूर- 570006, कर्नाटक	Tel: 91-821-2515149 Fax: 91-821-2500846	https://www. ksoumysore. edu.in/
8.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता (एनएसओयू), पश्चिम बंगाल- (1997)	1, वुडबर्न पार्क, कोलकाता- 700020, पश्चिम बंगाल	Tel: 91-33-22835157 Fax: 91-33-22835052	http://www. wbnsou.ac.in/
9.	यू.पी. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय (यूपीआरटीओयू), इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-1998	17, महर्षि दयानंद मार्ग (थॉर्नहिल रोड), इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	Tel: 91-532-2621840, 2623250 Fax: 91-532-2624368	http://www. uprtou.ac.in/
10.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय (टीएनओयू), चेन्नई, तमिलनाडु- (2002)	तकनीकी शिक्षा निदेशालय कैम्पस, गिन्डी, चेन्नई- 600025	Phone: 044-22351414 Fax: 044 2220 0601	http://www. tnou.ac.in/
11.	पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्व विद्यालय (पीएसएसओयू), बिलासपुर, छत्तीसगढ़- (2005)	पंडित दीन दयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, बिलासपुर (छत्ती सगढ़)-495001	Phone No: 07752 – 514255 Telefax : (0771) 2221259	http://www. pssou.ac.in/
12.	उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, (नैनीताल), उत्तरांचल	सौरभ माउंट व्यू के पास, भोतिया त्रोंव, हल्द्वानी – 263141, नैनीताल	Tel: +91 5946 263014, +91 5946 261123 Fax: +91 5946 264232	http://uou.ac.in/
13.	कृष्णकांत हांडीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम	हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, दिसपुर, गुवाहाटी- 781006, असम	Ph. No: (0361) 2235971, 2235642 Fax: (0361) 2235398	http://www. kkh sou.in/web/

(लेखक मीडिया शोधार्थी हैं और विज्ञान प्रसार से जुड़े हुए हैं) ■

ABVP NEC Meeting 28th to 30th May, Guwahati (Assam)

Divisive Politics Hindrance to Development of Nation

It's a matter of honor that Bharat is emerging as a strong nation thanks to its political will, able leadership and also Bharat has moved forward at international platform on economic, diplomatic, foreign policy and nation security subjects. However, because of vote bank politics, there is a concern that some emerging divisive powers are trying to weaken the nation which is moving forward on the path of development. Presently, leaders of various political parties are dividing the nation on the basis of caste, religion, region and social aspects, which are proving to be hindrance to the development of the nation. On account of this politics, raising doubts on the independence and credibility of the judiciary & other constitutional institutions, data thefts, credibility of banks, unemployment, Naxal activities and terrorism etc. are threat to the unity, integrity and development of this nation. ABVP believes that the central government has taken appreciable actions in this context on all these issues, but still continuous actions are required with a long term strategy.

Even to this day, various political parties are conspiring to divide Bharatiya society on the basis of caste, region and sect. There is no place for any kind of discrimination on the basis of caste or sect in the roots of Bharatiya culture. But at present religious reservation policy of Telangana government, similar divisive vote bank politics in Gujarat, Karnataka and other states and North-South region disputes in Tamil Nadu are against the constitutional values enshrined in the Indian Constitution. ABVP strongly condemns the attempt to divide the society by such political parties for vote bank politics. This NEC of ABVP is of clear opinion that during recent incidences like Bhima Koregaon (Maharashtra), The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 dispute and the Bharat Bandh incident of 2nd April, the patience and understanding shown by all the sections of the society, especially people belonging to the Scheduled Castes, is an example of a matured society. ABVP is of the firm opinion that SC/ST Act should be retained in its original form and no changes should be made currently.

Various parties have attacked the autonomy and transparency of constitutional institutions like Election Commission, Judiciary and other reputed organizations like ED, CBI, etc. which is of the grave

concern. This practice of pressurizing the judiciary by bringing impeachment motion and raising questions on its credentials is going to weaken the foundation of the constitutional system. Therefore, it should be stopped immediately. This National Executive Council of ABVP strongly criticizes and condemns the act of dragging judiciary in such disputes to gain political mileage.

The TMC government in West Bengal has repeatedly disobeyed the directions of Hon'ble High Court of West Bengal and challenged the higher constitutional institution of the nation. In the recently concluded Panchayat Polls of West Bengal, the leaders and workers of ruling party TMC have not allowed the opposition candidates to fill nomination in more than 16000 posts, have indulged in brutal killings and attacks on families of opposite party workers, attacks on assets, burning of homes, rapes of pregnant women and killing of election conducting officers (teachers) for conducting impartial election. This has made the West Bengal elections a black chapter in Indian Democracy. This NEC of ABVP demands from the central government to constitute a high level committee to enquire the same.

Data theft of Indian citizens by Cambridge Analytica has come into notice recently. Some powers are trying to use that data for widening the rift in the society on these grounds and conspiring to win elections. On the other side, negative campaign through social media and false literature in different states and educational institutes has given rise to the situation of internal conflicts. This is a serious challenge to healthy democracy and social harmony. This NEC of ABVP is of a clear opinion that the central government should initiate strict action in this regard and the youth of this nation must not be lured by all this, so that freedom of speech, social harmony and healthy democracy can be ensured.

ABVP demands from the central government that development work should be expedited to fulfill the expectations of the masses. ABVP urges all the sections of the society, specially the youth, media and academicians to play an important role in the development of the nation paying special attention to the development of SC and ST people. ABVP appeals to the SC/ST youth, other social organizations and political parties to come forward with full enthusiasm for the nation's development, so that India becomes a nation with security, self-esteem and self-reliance. ■

US-North Korea Relations: History in Making ?

| Swadesh Singh |

A second summit between US President Donald Trump and North Korea's Kim Jong-un may unfold in New York in September when the United Nations General Assembly (UNGA) is going to meet. The US administration is expected to push for this summit in its attempt to push for denuclearisation. The meet on American soil could be a major step ahead in this process but the chances of such a meet pin on how far North Korea is able to go in getting rid of its nuclear and ballistic weapons.

US-North Korea Agreement

On 12 June 2018, US President Donald Trump and North Korean (official name Democratic People's Republic of Korea (DPRK)) Chairman Kim Jong-un met in Singapore. The meeting was a landmark being the first such since 1950 when the Korean War broke out, dividing the peninsula divided into a communist north and a liberal-democratic south.

The meeting resulted in an agreement on termination of Korean War hostilities which continue to persist six decades after the war had technically ended. The agreement also outlined the denuclearization of the peninsula with complete denuclearisation expected to take roughly one year to accomplish.

While reaching out to the North Korean regime and expressing confidence that Kim will live up to his end of the deal, the US President maintained a firm stand saying that sanctions will be lifted once nuclear weapons are no longer a factor. Trump also said he had planned to place another 300 sanctions on

North Korea recently, but he held off because it would be disrespectful ahead of the meeting.

At a news conference soon after meeting Kim face to face, Trump said: 'Real change is indeed possible. I am prepared to start a new history and write a new chapter between the two nations.' He also said that the past does not have to define the future.

The agreement says, 'The United States and the DPRK commit to establish new US-DPRK relations in accordance with the desire of the peoples of the two countries for peace and prosperity. The United States and the DPRK will join their efforts to build a lasting and stable peace regime on the Korean Peninsula. Reaffirming the April 27, 2018 Panmunjom Declaration, the DPRK commits to work toward complete denuclearization of the Korean Peninsula. The United States and the DPRK commit to recovering POW/MIA remains, including the immediate repatriation of those already identified.

The History of US-North Korea Relations

A three-year war in the early 1950s saw the two countries pitted against each other. The war, that claimed millions of lives including 36,000 US soldiers, had broken out in June 1950 when North Korean troops launched a surprise assault on the South by crossing the 38th parallel. Unequipped to deal with the escalation, the South Korean military was almost driven off the peninsula when the US-led UN forces intervened and pushed back invaders. The geo-political equations of the region came into play as the Chinese military too intervened, pushing the UN forces back. In July 1953 the war was brought to an end with the signing of an armistice. However, the armistice has not been replaced with a peace

treaty, leaving the peninsula in a technical state of war with about 28,500 US soldiers still stationed in South Korea.

In the summer of 1976, two US soldiers were hacked to death by axe-wielding North Korean soldiers during a fight over US efforts to trim a poplar tree in the Demilitarized Zone that bisects the Koreas. In June 1994, former US President Jimmy Carter travelled to North Korea and had two rounds of lengthy talks with Kim Sung Il in an effort to resolve an early round of nuclear confrontation. In October 2000, Kim Jong Il's right-hand man and vice marshal, Jo Myong Rok, flew to the United States, becoming the most senior North Korean official to visit its wartime foe since the end of the Korean War. A few weeks after Jo's trip, US secretary of state Madeleine Albright made a reciprocal visit to Pyongyang to try to arrange a North Korea visit by Clinton. The reconciliatory mood between the two countries shifted dramatically after President George W. Bush took office in January 2001 with a tough policy on the North. Clinton eventually went to North Korea as a former president in 2009 to secure the freedom of two detained American journalists held there.

Kim changed tactics in 2018, sending a delegation to the Winter Olympics in the South and holding a summit with South Korean president Moon Jae-in. Kim has offered to negotiate away his nuclear program if he's provided with a reliable security guarantee from the United States.

The China Factor

North Korea enjoys a good relationship with China. Chairman Kim visited China following a meeting with President Trump. What transpired at the meeting between the Chinese and Korean leaders was not officially revealed however, it was expected that they discussed sanctions and Kim's general commitment to denuclearise the Korean peninsula.

China, North Korea's only economic ally, has suggested that sanctions against the nation could be eased. On the other hand,

the US confirmed the suspension of next joint military drills with South Korea as a confidence building measure with North.

The visit to China is Kim's third since March, when his first trip abroad since taking office was to meet President Xi Jinping.

Good News for India

Donald Trump-Kim Jong Un meet is good news for India. In a statement, Ministry of External Affairs expressed 'hope that the outcomes would be implemented, thus paving the way for lasting peace and stability in the Korean Peninsula. We also hope that the resolution of the Korean Peninsula issue will take into account and address our concerns about proliferation linkages extending to India's neighbourhood.'

The Ministry of External Affairs (MEA) at the same time hoped that any resolution to the North Korean "peninsula issue" will address New Delhi's concerns about Pyongyang's proliferation linkages with India's neighbourhood, seen as an apparent reference to Pakistan. India has been pressing for a probe into North Korea's proliferation linkages with India's neighbourhood.

The thaw in US-North Korea relations will definitely bring peace in Asia and the world. India will also be benefitted indirectly as China is believed to route its weapons through North Korea to Pakistan. China, that is known to use North Korea as its 'bad' hand, has been supporting the Communist country in the face of any stalemate against the western powers especially USA. US should factor in China angle while negotiating with North Korea. It must assure North Korea of maintaining equal relations with the both the countries of the peninsula and guarantee that the interests of the North Korea would be taken care of both domestically and globally. With the 'end of ideology' proving to be true and clash of civilisations becoming the dominating discourse, the stage is set for a new beginning in US-North Korea relations. ■

(Author teaches Political Science in Satyawati College of Delhi University.)

ABVP NEC Meeting 28th to 30th May, Guwahati (Assam)

Review & Immediate Execution of Scholarships: Need of Hour

Scholarships awarded for research and several other courses to the students are not only important for instant educational needs but also for improving the quality of research.

Timely distribution of scholarship and considerable increase in amount of scholarship with time is essential for encouraging education and providing suitable opportunities. The rate of scholarships distributed since the commencement of scholarship schemes and the number of student beneficiaries requires thorough review with the passage of time. The increase in price index and number of students since the commencement of scholarship schemes should be the criteria for reviewing these scholarship schemes. Due to continuous agitations and concern of ABVP, the JRF amount has been increased from Rs. 16000 to Rs. 25000 and the SRF amount has been increased from Rs. 18000 to Rs. 28000.

Irregularities in execution of scholarship schemes have resulted in continuous decrease in distribution of BSR fund and National Fellowship Scheme (RGNF before) for past 3 years. Students are denied scholarships due to problems persisting in submission of online forms. Only 750 ST and 2000 SC students are benefitted every year from National Fellowship Scheme (RFNF). This number must be immediately increased.

To ensure fair mechanism in distribution of scholarships, it must be ensured that the amount of scholarship is transferred to the student at the beginning of academic year. Continuous irregularities, deficiency in evaluation, delayed execution, different distribution strategies followed by different funding agencies like UGC, CSIR, DST, DBT are matters of concern. ABVP demands establishment of a separate commission for combating such problems.

No increase in Non-NET fellowships is a matter of concern for all the students. Increase in Non-NET fellowships with a clear policy on the basis of price hike and current needs is required. Equal opportunities for Non-NET fellowship which is

limited to central universities with its expansion to all state universities must be done.

Scholarship provided in pre-matric to day-scholars is Rs. 150 per month and Rs. 350 per month for hostellers. Similarly, maximum scholarship provided in post-matric to day scholars is Rs. 550 and Rs. 1200 to hostellers. Both of these are very low in today's context. ABVP demands that central government should increase these scholarships by 3 times.

Fellowships provided to young scientists for research purpose under PMRF have turned out to be a positive approach to develop research environment in the country. ABVP welcomes and appreciates this initiative by the government.

No reconsideration has been done by institutes like UGC, CSIR, DST, DBT on research fellowships like JRF, SRF Research Associate, NPDF (National Post-Doctoral Fellowship) since 2014. Reconsideration should be necessarily done with an analysis of difference between amounts in 2014 and today. Scholarship schemes must be regularly reviewed to promote research in the country.

Fraudulent transactions from fake accounts created by some money-minting colleges/institutions and non-distribution of Utilization Certificates during Central Scholarship Fund 2004-2014 point towards the widespread mess-up which is a matter of grave concern. ABVP demands a high level investigation into such scandals.

ABVP urges the government to make universities accountable and answerable for the undistributed scholarships in universities. ABVP also demands that information of all kinds of scholarships should be made available in public domain through websites so that it is easily accessible to the students.

ABVP is continuously working to provide equal opportunities to all the students for scholarships. ABVP seeks support of student community in our demand to control irregularities and promote proper execution of scholarship schemes in the larger interest of students' welfare. ■

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अभाविप का प्रदर्शन

अ

खिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के रायसीना रोड स्थित मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ था। बता दें कि फिरोज खान पर उनके ही संगठन की एक कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठी भंजने के कारण अभाविप के कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। अभाविप, दिल्ली के प्रदेश मंत्री भरत खटाना के मुताबिक एनएसयूआई की छात्रा कार्यकर्ता ने फिरोज खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एनएसयूआई अध्यक्ष की सोच महिला विरोधी है। पद देने के नाम पर अपने ही संगठन के छात्राओं को अपने पास गलत तरीके से बुलाते हैं। जब



तक वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई का इतिहास महिला विरोधी रहा है। इस घटना से फिर एक बार उनका चरित्र उजागर कर दिया है। अगर संगठन के सर्वोच्च नेता का चरित्र सवालियों के घेरे में हो तो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की महिलाओं को लेकर क्या सोच होगी। ■

खूंटी में सामूहिक दुराचार के विरोध में अभाविप का आक्रोश मार्च

झा

खंड के खूंटी में महिला रंगकर्मियों के साथ पत्थलगड़ी समर्थकों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के द्वारा जिला स्कूल रांची से लेकर राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला गया। इसमें विभिन्न कॉलेजों के लगभग चार सौ छात्र - छात्राएं शामिल थे। छात्राएं सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों पर कार्रवाई और संबंधित संस्थानों पर प्रतिबंध की मांग कर रही थी। अभाविप की ओर से मांगों से संबंधित एक ज्ञापन राज्यपाल को भी सौंपा गया।

छात्राओं ने पत्थलगड़ी की आड़ में चर्च प्रेरित संगठनों पर जनजातीय समाज का शोषण करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्र - छात्राओं ने हाथों में तख्तियां ले रखीं थीं। राजभवन के पास पहुंचने पर प्रदर्शनकारी छात्राओं ने पुलिस की

बैरकटिंग को तोड़कर आगे बढ़ना चाहा। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उनके साथ जमकर बहस हुई। आक्रोशित छात्राएं पुलिस की बैरकटिंग को तोड़कर लगभग पचास मीटर तक आगे बढ़ गईं। इसके बाद छात्राओं को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। परिषद् के प्रांत संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि पत्थलगड़ी की आड़ में दुराचार स्वीकार नहीं है। चर्च व नक्सली राज्य को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है।

प्रदर्शनकारियों ने फादर अल्फांसो सहित सभी दुष्कर्मियों को फांसी देने की मांग करते हुए खूब नारेबाजी की। अभाविप के कार्य समिति सदस्य अशोक मुंडा ने कहा कि खूंटी में चर्च की सच्चाई सबके सामने है। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्थलगड़ी के आरोप की आड़ में जनजातियों का शोषण खुलेआम किया जा रहा है। ■

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय से प्रणब दा के सन्देश का निहितार्थ

। हर्षवर्धन त्रिपाठी।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय में हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और संघ प्रमुख मोहन राव भागवत के संबोधनों को राजनीतिक नजरिए से देखने की कोशिश हो रही है। लेकिन दोनों ने अपने उद्बोधन में जो बातें कहीं हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है। इसकी साफ सी वजह ये है कि प्रणब मुखर्जी के नागपुर जाने को लेकर राजनीति बहुत हावी हो गई थी। ये इस कदर हावी हो गई कि खुद उनकी बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी को ट्वीट कर कहना पड़ा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसका इस्तेमाल करता रहेगा। ये जो इस्तेमाल करने की बात हो रही है कि तो उसे अगर ठीक से समझा जाए तो महात्मा गांधी संघ के शिविर में गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गए। राष्ट्रपति गए। पूर्व राष्ट्रपति गए। कलाम साहब गए। जेपी उनके शिविर में जाते रहे। अब प्रणब मुखर्जी उनके कार्यक्रम में गए।

सबसे बड़ी बात ये है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को लेकर एक खास छवि बनाई जाती रही है। संघ को इस तरह से खांचे में बांध दिया गया कि जैसे वो देश को पूरी तरह से तोड़ देना चाह रहा है। खंडित कर देना चाह रहा है। कम से कम उस चर्चा पर विराम पहले से लगना चाहिए था। शायद इसीलिए कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर डर लगता है कि वो जिस तरह से फासले बना चुका है। संघ विरोध में खड़ी हो चुकी है। स्वयं सेवकों को राजनीतिक नजरिए से देखती है। उनको बीजेपी के करीब देखती है। शायद सारी मुश्किल वहीं से खड़ी हुई है।

प्रणब मुखर्जी का उद्बोधन संघ के तृतीय वर्ष के शिक्षा वर्ग में हुआ। ये शिक्षा वर्ग हर साल होता है। देश भर से स्वयं सेवक इसमें जाते हैं। पहले से ही इस कार्यक्रम में समाज के बड़े-बड़े लोग बुलाए जाते रहे हैं। संघ चालक ने मंच से इसका इस तरह से जिक्र किया कि समाज की जो भी सज्जन शक्तियां हैं, जो बड़े लोग हैं। जिन्हें सुन सकते हैं। उन्होंने पाथेय शब्द का इस्तेमाल किया। अगर



प्रणब मुखर्जी के कहे को वो इस तरह से मान रहे हैं तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आखिर उसको अपने उस नेता को, जिसने पूरा जीवन कांग्रेस को दिया, उनके संघ के कार्यक्रम में जाने का क्या फायदा हो रहा है। यहां जवाब लें उससे पहले इसका जिक्र जरूरी है कि ये सब जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी पीएम पद के सबसे काबिल दावेदार थे। लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया। कई बार लगा कि प्रणब मुखर्जी को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है। आखिर में वे राष्ट्रपति बने। अब जवाब जान लें कि प्रणब मुखर्जी के नागपुर के रेशमबाग पहुंचने से हिंदुस्तान मजबूत हुआ है। भारत मजबूत हुआ है। भारतीयता मजबूत हुई है। राष्ट्रवाद मजबूत हुआ है और देशभक्ति को समझने का नजरिया व्यापक हुआ है।

अगर मेरी बात पूरी तरह से समझ में ना आए तो एक बार फिर से पहले मोहन भागवत और उसके बाद प्रणब मुखर्जी को सुनिए। लगता है कि पहले उद्बोधन का वस्तु ही दूसरा है। जो बातें प्रणब मुखर्जी ने कही कि यही बात सिर्फ मोहन भागवत बोल रहे होते कि यूरोप से हमारी अच्छी संस्कृति है तो वामपंथी विचारक इसका छद्मनिष्पेक्षण करते कि इन्हें कुछ नहीं आता। यूरोप तो बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने बताया कि फाह्यान से लेकर दुनिया भर के विदेशी यात्री आए। उन्होंने भारत की बुनियादी सुविधाओं को सबसे अच्छा

बताया। यहां को प्रशासन को दुनिया भर में बेहतरीन बताया। प्रणब मुखर्जी ने सैकड़ों सालों की दासता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम पर मुगलों ने राज किया। बड़ी दासता रही। अंग्रेजों ने राज किया। लेकिन हम फिर भी नहीं बदले। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। भारतीय संस्कृति का जिक्र किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जिक्र किया। रवींद्र नाथ टैगोर का जिक्र किया। यही सब जब हम मिलकर करते हैं तो यही हिंदुस्तान बनता है। यही भारत बनता है। राष्ट्रीय सेवक संघ ने कभी ये बात नहीं कही।

जाहिर है कि मोहन भागवत ने कहा कि हमें जो काम करना है उसके लिए शक्ति चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शक्ति पर अगर ज्ञान नहीं होगा। शील नहीं होगा। विवेक नहीं होगा। तो वो दानव शक्ति बन जाएगी। इस छोटी सी बात को हमें समझना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी का जाना। प्रणब मुखर्जी सारा जीवन कांग्रेसी रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कमाल के उदाहरण पेश किए। न सिर्फ उन्होंने आम जन के लिए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे खोले। न सिर्फ सिटिजन प्रणब लिखते रहे। बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आज से मैं राजनीति से ऊपर उठ गया। राष्ट्रपति बन गया। संवैधानिक पद पर पहुंचे व्यक्ति के लिए यही इस देश की व्यवस्था होनी चाहिए।

जब प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि हिंसा का स्थान नहीं है। असहष्णुता का स्थान नहीं है। तो अगर उग्र हिंदुत्व के नाम पर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये उनको संदेश है। कांग्रेस को भी ये संदेश है। प्रणब मुखर्जी के संघ मुख्यालय जाने पर कांग्रेस ने क्या किया। खबरें तो यहां तक आयीं कि सोनिया गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया था। उन्होंने लोगों से चिट्ठियां लिखवाईं। ट्विट करवाएं। यहां तक कि शर्मिष्ठा मुखर्जी से कहा कि तुम्हें ट्वीट करना चाहिए। अगर ये स्थितियां बनीं तो ये कितनी खतरनाक है कि देश में हिंसाए गुस्से और असहष्णुता को भुनाने की कोशिश हो रही है। सवाल यही उठे

कि इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा। बीजेपी को कितना फायदा होगा। लेकिन यहां सवाल ये नहीं था। राजनीतिक दलों को फायदा मिले ना मिले लेकिन वो अपने फायदे के लिए निरंतर काम करती रहती हैं।

राष्ट्रीय स्वयं संघ के मंच पर प्रणब मुखर्जी का जाना। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को भारत माता का महान सपूत बताते हुए श्रद्धांजलि देना। ये हिंदुस्तान के मजबूत होने की बात करता है। राष्ट्र के मजबूत होने की बात करता है। यही हिंदुस्तान है। यहीं विचारों का आदान प्रदान हमारी संस्कृति है। हमारी पहचान है।

याद कीजिए जब बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बुलंद कर रही थी तो मोहन भागवत ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत हमारा नारा नहीं है। ये अलग बात है कि इस नारे से दशकों पहले 1925 से ही संघ की स्थापना के बाद ही लगातार ये साजिश होती रही कि संघ मुक्त भारत हो जाए। लेकिन मोहन भागवत ने कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ इससे कुछ नहीं होना है। जो भारत को रास्ता दिखाना है। जो दुनिया को रास्ता दिखाना है। उसके लिए हमें अपना एक उदाहरण पेश करना होगा। हम कैसे व्यवहार कर

रहे हैं।

ये जो व्यवहार की बात होती है कि हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं। यहीं संघ की ताकत है। यहीं हिंदुस्तान की ताकत है। राष्ट्र, राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर भाषणों से अलग व्यवहार ही दिखाता है। इसलिए कांग्रेस को इसे समझना चाहिए। दूसरे दलों को भी समझना चाहिए। राजनीति आप राजनीतिक नजरिए से करिए। लेकिन कम से कम देश को दो बड़े विचारवान लोग जिन्होंने समाज में बड़े बदलाव किए हैं उनकी बात सुनिए। समझने की कोशिश करिए। कुल मिलाकर 7 जून की शाम रेशमबाग प्रणब मुखर्जी का जाना ताकतवर होते हिंदुस्तान की बुनियाद में एक और मजबूत होती ईंट का जुड़ना है। ■

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)



अंधेरे में “पूनम का चांद” है गुरु

| अजीत कुमार सिंह।

“अ ज्ञान तिमिरांधश्च ज्ञानांजन शलाकया ।
चक्षुन्मीलितम् तस्मै श्री गुरुवे नमः॥”
- हमारे शास्त्रों में गुरु का अर्थ अंधकार
अथवा मूल अज्ञान और गुरु का अर्थ
उसका निरोधक बताया गया है। गुरु को गुरु कहने
के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। गुरु अज्ञान
के तिमिर को ज्ञानंजन शलाका से निवारण कर देता है
यानी अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर
ले जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के
रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा को चुनने
के पीछे गहरा अर्थ है, इसका अर्थ है कि गुरु पूर्णिमा
की चांद की तरह हैं जो पूर्ण प्रकाशमान है और उसके
शिष्य आषाढ़ के घने बादलों की तरह। गुरु के पास चांद
की तरह जीए गए अनुभवों का अक्षय भंडार होता है।
इसीलिए इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। घने बादलों
अर्थात् शिष्यों के बीच घिरे रहने के बावजूद भी गुरु
चांद की तरह चमकता रहे, शिष्यों को राह दिखा सके,
अज्ञानता के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश में बदल सके,
गुरु की श्रेष्ठता है। तभी तो सनातन (हिन्दू) शास्त्रों में
गुरु को भगवान से ऊपर आंका गया है।

गुरु की महिमा को कबीर दास के दोहे से सहज
समझा जा सकता है। कबीर दास ने कहा है कि -

“गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके लागूं पांव, बलिहारी
गुरु आपने, जिन्हें गोविन्द दियो बताय॥”

अर्थात् गुरु और गोविन्द यानि ईश्वर दोनों एक
साथ खड़े हैं, शिष्य उधेड़बुन में है कि मैं सबसे पहले
किसे प्रणाम करूं क्योंकि मेरे लिए तो गुरु, ईश्वर से
भी बड़े हैं। अपने शिष्य की शंका को देखते हुए गुरु ने
गोविन्द के पांव छूने का ईशारा कर दिया। गुरु की महिमा
अपरंपर है। गुरु के बिना, ज्ञान की प्राप्ति असंभव है।
गुरु की महिमा के बारे में बखान किया जाय तो शास्त्रों
के मुताबिक अगर भगवान से कोई श्रापित है तो उसे गुरु
बचा सकता है लेकिन अगर कोई गुरु से श्रापित है तो
उसे भगवान भी नहीं बचा सकता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु
की पूजा करने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है।
पूरे भारतवर्ष में इसे बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।
प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम जाते थे तो
गुरु उन्हें निःशुल्क शिक्षा दान देते थे अतः वे साल में
एक दिन गुरु की पूजा करके अपने सामर्थ्य के अनुसार
उन्हें दक्षिणा देते थे। ग्रंथों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन
महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ है। वेदव्यास जी ने 18
पुराणों एवं 18 उपपुराणों की रचना की थी। महाभारत

एवं श्रीमद्भागवत इनके रचित शास्त्र हैं। इसीलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है।

भारतीय संस्कृति में गुरु का विशिष्ट स्थान है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान समझकर सम्मान करने की भारतीय पद्धति चिर पुरातन है। लेकिन पाश्चात्य देशों में गुरु का कोई विशेष महत्व नहीं है वहां पर विज्ञान और विज्ञापन का महत्व है। गुरु - मार्गदर्शक, जीवनरक्षक, प्रेरक और ज्ञान का द्योतक है। उनका जीवन शिष्य के लिए आदर्श बनता है। उनकी सीख जीवन का उद्देश्य बनती है। गुरु यानी अंधकार में दीप, सागर में द्वीप, मरुस्थल में वृक्ष और हिमखंडों के बीच अग्नि बनकर शिष्यों को निहाल करने वाला। भारत में धन से ज्यादा चरित्र को महत्व दिया गया है। प्राचीनकाल में गुरु शिष्य को सांसारिक, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ - साथ चारित्रिक शिक्षा का ज्ञान देते थे, जिस कारण भारत विश्वगुरु हुआ करता था। गुरु यानी जो शिष्य के कानों में ज्ञानरूपी अमृत का सिंचन करे और धर्म के साथ - साथ चरित्र का रहस्योद्घाटन करे, उत्थान करे, वही सच्चा गुरु है। यह जरूरी नहीं कि हम किसी व्यक्ति को ही गुरु बनाएं। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने भगवा ध्वज को अपना गुरु माना है और उसी ध्वज को आदर्श मानकर रोज उसे प्रणाम करता है। रा. स्व. संघ के द्वारा भगवा ध्वज को गुरु मानने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। एक बार मैंने इसके बारे में संघ के बड़े अधिकारी से चर्चा भी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि संघ किसी व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। इसीलिए संघ के आद्य सर- संघचालक डॉ. केशव बलीराम हेडगवार जी ने भगवा ध्वज को अपना गुरु माना। भगवा यानी त्याग, समर्पण, ओज, वीरता का प्रतीक... जो समस्त समाज को एक सूत्र में बांधकर विश्वबंधुत्व का नारा दे सके। संघ के स्वयंसेवक गुरु पूर्णिमा के दिन अपने सामर्थ्यनुसार गुरु दक्षिणा देते हैं और इसी गुरु दक्षिणा से संघ के कार्य चलते हैं।

विद्यार्थी परिषद् हमेशा से भारत के अनुरूप शिक्षा नीति लाने की बात करती है और इसके लिए संघर्षरत भी है। कालांतर में भारतीय शिक्षा पद्धति में काफी बदलाव आया है। महान दार्शनिक ओशो ने जब यह कहा कि हमारी शिक्षण संस्थाएं अविद्या का प्रचार कर रही हैं तो लोगों ने जमकर इसका विरोध किया लेकिन ओशो गलत नहीं थे वे दूरदर्शी थे, सही बात कह रहे थे। आज

हमारे विद्यालयों में ज्ञान का नहीं बल्कि सूचनाओं का प्रवाह हो रहा है। छात्रों का ज्ञान से दूर - दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा। पढ़ाई का मतलब नौकरी पाना और धन संग्रह करना हो गया है। इसीलिए आज हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, न्यायाधीश, वकील और वास्तुकारों की तो एक बड़ी भीड़ जमा है लेकिन ज्ञान के अभाव में चरित्रवान समाज की कल्पना दिवा-स्वप्न बनकर रह गई है।

शिक्षा का संबंध यदि चरित्र न होकर धन संग्रह हुआ तो उसका परिणाम यही होगा। लेकिन इस मूल प्रश्न की ओर ध्यान कौन दे? सरकार शिक्षा का संबंध चरित्र के बजाय रोजगार से जोड़ना चाहती है। लोगों के मन में भी पढ़ाई का संबंध एक मात्र उद्देश्य रोजगार पाना रह गया है। जीविकोपार्जन के लिए रोजगार का होना नितांत आवश्यक है लेकिन शिक्षा को व्यापार बना देना कहां तक उचित है? जो लोग शिक्षा का संबंध रोजगार से जोड़ने की बात करते हैं, वे वस्तुतः वर्षों - वर्षों तक राज करने के लिए अपनी भूमिका तैयार कर रहे हैं और उनके तर्क जन साधारण को संजीवनी महसूस होता है, जबकि उनके तर्कों के पीछे उद्देश्य कुछ और है। आज हमारे देश में मैकालियन के तथाकथित औलादें देश की दशादिशा तय कर रहे हैं जिन्हें न भारत के बारे में ठीक से पता है और न भारतीयता का...यही कारण है देश में अनैतिकता, अराजकता, हिंसा, यौनाचार और आतंक बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार और अपराध जीवनशैली बन गई है। मां - बाप वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी काटने के लिए विवश हैं। लोगों में इंसानियत और भाईचारे खत्म हो रहे हैं, देश के विरुद्ध नारे लग रहे हैं और नारे लगाने वाले को तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा महिमामंडित किया जा रहा है। समाज सेवा के नाम पर चल रही कुछ मिशनरियों के द्वारा बच्चों को बेचने का गोरखधंधा किया जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को कट्टर बनाया जा रहा है। कश्मीर में अपने ही जवानों पर पत्थर फेंका जा रहा है। इसका मूल कारण गुरु को नकारकर, चरित्र को भूलाकर हमने केवल भौतिकता को जीवन का आधार बना लिया है। यदि हमें भारत के पुराने वैभव को प्राप्त करना है तो चरित्र निर्माण पर बल देना होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम भारत में कौन सी पद्धति लागू करें बल्कि महत्वपूर्ण यह कि चरित्रवान व्यक्ति पैदा करें। चरित्र का निर्माण बिना गुरु के संभव नहीं है। ■

ABVP NEC Meeting 28th to 30th May, Guwahati (Assam)

Consistent Efforts Necessary for Women Dignity

This National Executive Council of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad welcomes the present central government's implementation of women centric schemes like 'Mudra Yojana', 'Ujwala Yojana', 'Sukanya Samridhi Yojana' and 'Beti Bachao, Beti Padhao' etc. and effective efforts in Triple Talaq Bill. This year the performance of women in Commonwealth Games, Circumnavigation by Team Tarini under the leadership of Lt. Cdr. Vartika Joshi, Climbing of Mount Everest by 16 year old Shivangi Pathak, Manisha Dhurve and Moore Linge, fighter plane flying by flying officer Avani Chaturvedi are all appreciable examples that make us proud. These examples reflect that the people of our society have accepted the changes with enthusiasm.

This NEC of ABVP believes that on one side Indian women are setting new trends whereas on the other side the incidences of sexual offences and harassment have become a challenge for their dignity. Some people have been playing caste and religion politics in the garb of providing justice to the victim in some cases that occurred in the recent past.

This NEC of ABVP is of clear opinion that the dignity of women should be restored and therefore, women should get the right of equal opportunity, participation in decision making and economics independence.

1. With the objective of women empowerment,

taking inspiration from Mission SAHASI, girls should be trained to be fearless, to deal with tough circumstances with confidence and to find their way out.

2. To prevent violence against women and to make them legally aware of their rights, workshops at district and village level should be organized.

3. Fast-track courts should be constituted for trial of rape like brutal offences against women.

4. The 108th Amendment of Indian

Constitution regarding Women Reservation Bill should be passed so that 33 percent participation of women in parliament can be ensured. It should be implemented in Vidhan Sabha and Vidhan Parishad as well.

5. Cyber harassment cases like passing of lewd, disrespectful comments against women should be firmly dealt with under cyber laws. For that, more stringent provisions should be made in cyber laws.

6. The central government should take necessary steps to ensure utilization of Nirbhaya Fund.

7. Amendment to the POCSO Act should be implemented without any gender discrimination.

8. The central government should take effective steps for easy and affordable access to biodegradable sanitary napkins.

9. Although there exist tough laws, the incidences of women harassment are rapidly increasing. A widespread campaign to create awareness for dignity and respect for women should be done to reduce such harassment incidences. ■

This NEC of ABVP believes that on one side Indian women are setting new trends whereas on the other side the incidences of sexual offences and harassment have become a challenge for their dignity. Some people have been playing caste and religion politics in the garb of providing justice to the victim in some cases that occurred in the recent past. This NEC of ABVP is of clear opinion that the dignity of women should be restored and therefore, women should get the right of equal opportunity, participation in decision making and economics independence.

शहरी नक्सलियों का खतरा

। संजीव कुमार सिन्हा ।

इ

स साल जनवरी में पुणे के भीमा-कोरेगांव में भयंकर हिंसा हुई थी। इस हिंसा की जांच कर रही पुणे पुलिस को जो सबूत मिले, वे चौकाने वाले रहे और चिंतित करने वाले भी। पुलिस को पता चला कि शहरी क्षेत्रों से नक्सलवाद को समर्थन मिल रहा है और एक पत्र सामने आया जिसमें खुलासा हुआ कि ये साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची जा रही है।

18 अप्रैल को रोणा जैकब द्वारा कॉमरेड प्रकाश को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि हिंदू फासिज्म को हराना अब काफी जरूरी हो गया है। मोदी की अगुवाई में हिंदू फासिस्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में उन्हें रोकना जरूरी हो गया है।

पत्र में लिखा गया है कि मोदी की अगुवाई में भाजपा बिहार और बंगाल को छोड़ करीब 15 से ज्यादा राज्यों में सत्ता में आ चुकी है। अगर इसी तरह ये रफ्तार आगे बढ़ती रही तो माओवादी पार्टी को खतरा हो सकता है।

पत्र में आगे कहा गया है, “मोदी राज का अंत करने कॉमरेड किशन और कुछ अन्य वरिष्ठ कॉमरेड्स ने कड़े कदम अर्थात् ‘कॉन्क्रीट स्टैप्स’ सुझाये हैं। हम राजीव गांधी जैसी एक और घटना के बारे में सोच रहे हैं।”

कहा गया, ‘अगर ऐसा होता है तो ये एक तरह से सुसाइड अटैक लगोगा, हमें लगता है कि हमारे पास ये चांस है। मोदी के रोड शो का टारगेट करना एक अच्छी प्लानिंग हो सकती है।’

गौरतलब है कि 21 मई 1991 को आम चुनावों के समय प्रचार करने तमिलनाडु के श्री पेरुंबुदूर पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उग्रवादियों ने आत्मघाती विस्फोट के जरिए हत्याम कर दी थी।

पत्र के विषयवस्ती से नक्सलियों के दुस्साहस और षड्यंत्र का सहज ही पता चलता है।

विदित हो कि पुणे पुलिस ने दिसंबर 2017 में पुणे में एक सभा में भड़काऊ भाषणों के सिलसिले में बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान गिरफ्तार लोगों में मुंबई के सुधीर धवले, नागपुर के वकील सुरेंद्र गाडलिंग और दिल्ली के कार्यकर्ता रोना जैकब विल्सन शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने नागपुर में शोमा सेन और मुंबई में महेश राउत को भी गिरफ्तार किया। विल्सन को महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए

गए संयुक्त अभियान के तहत दक्षिणी दिल्ली के एक इलाके से गिरफ्तार किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र विल्सन मुनिरका के पास एक डीडीए फ्लैट में छिपे हुए थे।

गिरफ्तार लोगों में धवले मराठी पत्रिका ‘विद्रोही’ के संपादक हैं। गाडलिंग प्रमुख नक्सली कार्यकर्ता जी.एन. साईबाबा की तरफ से न्यायालय में पेश हुए थे और कबीर कला मंच को कानूनी सहायता मुहैया कराई थी। इसी मंच ने एलगार परिषद का आयोजन किया था। राउत प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास का फेलो रह चुके हैं और उनके महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली समूहों से संबंध हैं।

गिरफ्तार लोगों ने पिछले वर्ष 31 दिसंबर को पुणे के शनिवारवाड़ा में एलगार परिषद आयोजित किया था। यह परिषद ब्रिटिश सेना और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध की 200वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई थी।

इस आयोजन को गुजरात के दलित नेता व विधायक जिगनेश मेवानी, जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद, छत्तीसगढ़ की सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी और भीम सेना के अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने संबोधित किया था।

इसके एक दिन बाद एक जनवरी को कोरेगांव-भीमा में दंगे भड़के उठे थे।

इसके पहले नक्सलियों से सहयोग करने के जुर्म में सात मार्च 2018 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की एक अदालत दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईबाबा, जेएनयू के छात्र हेम मिश्रा, पत्रकार प्रशांत राही समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। कोर्ट ने इन सभी को माओवादियों से संपर्क रखने और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का दोषी करार दिया था।

आधी शताब्दी से नक्सली गिरोह सक्रिय है। उनके पास अत्याधुनिक हथियार और संचार साधन हैं। आदिवासियों एवं गरीबों की आड़ में ये रंगदारी, लूट, स्म लिंग के जरिए अवैध कमाई करने में जुटे हैं। इसी साल 12 जनवरी को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने नक्सली इलाकों के पुलिस अफसरों की बैठक बुलाई थी। इसमें प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी शामिल हुई थी। इससे पता चला कि नक्सलियों ने रंगदारी और नशे के कारोबार के जरिए काफी कमाई की है। कुछ दिनों पूर्व की ही खबर है कि नक्सली झारखंड में 500 एकड़ में गांजा और

अफीम की खेती करा रहे थे, जिससे उन्हें 55 करोड़ रूपए की आमदनी हो सकती थी। झारखंड सरकार और सीमा सुरक्षा बल को इसका पता चला तो इसी साल मार्च में उसे नष्ट करा दिया।

इतना ही नहीं, नक्सली इलाकों के भोले-भाले लोगों को हथियार उठाने के लिए बरगलाते हैं और मौका आने के बाद उन्हीं की लड़कियों या गुरिल्ला दल में शामिल अपनी साथियों को ही सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं।

नक्सली दावा करते हैं कि वे आदिवासियों और गरीबों का हित चाहते हैं। लेकिन ध्यातव्य है कि उनके हिंसक संघर्ष से ज्यादा नुकसान आम लोगों का ही हुआ है। आए दिन यह देखने को मिल रहा है कि नक्सली किस तरह विकास के कामों में बाधा पहुंचाते हैं। सड़क, संचार-सेवा, विद्यालय सबको वे बम से उड़ाकर ध्वस्त कर देते हैं।

दरअसल, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्वहवाली केंद्र सरकार के कड़े रुख के चलते नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हो गई है। इससे उनके हौसले पस्त हैं। नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से 44 जनपद बाहर हो गए हैं।

शहरों में नक्सलवाद के बढ़ने का सबसे पहला मामला केरल में लोगों के सामने आया जब एक नक्सल वर्ग को पुलिस ने पकड़ा था। जिसमें यह बात सामने निकलकर आयी थी कि ये लोग शहरों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। यही नहीं इन नक्सलियों की आगे की योजना चेन्नई में अपने काम को मजबूत करना और नेटवर्क का विस्तार करना था। वहीं खुफिया विभाग की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि कई बुद्धिजीवी इन नक्सलियों की मदद करते हैं।

कर्नाटक के बेंगलूरु में महाविद्यालयीन शिक्षा ग्रहण करने के दौरान कॉमरेड साकेत राजन से प्रभावित 34 वर्षीय अभय ने साकेत राजन की मृत्यु के पश्चात माओवादी साहित्य तैयार करने, विज्ञप्ति जारी करने और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को सरकार विरोधी गतिविधियों से जोड़ने का काम करता था। अभय इंडिया माइक्रो फायनेंस के नाम से ब्लॉग संचालित करता था तथा अंतरराष्ट्रीय आतंकी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का भी करता था।

प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौर के दो दिन पूर्व पुलिस ने जगदलपुर में नक्सलियों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भांडाफोड़ कर आईटी के बड़े जानकार नक्सली नेता अभय देवदास नायक उर्फ लोड्डा को गिरफ्तार किया। यह नक्सली बड़े-बड़े शहरों में नक्सल विचारधारा के प्रचार-प्रसार में इस नक्सली की अहम भूमिका है व माओवादी साहित्य तैयार करता था।

यह चिंताजनक है कि बर्बर नक्सलियों को वैचारिक

खुराक शहरों में रहनेवाले प्रोफेसर, पत्रकार, लेखक मुहैया करा रहे हैं। ये कथित बुद्धिजीवी अधिक खतरनाक हैं। ये मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का राग अलापते हुए नक्सलियों को 'बंदूकधारी गांधीवादी' कहकर महिमामंडित करते हैं। जब भी नक्सली सामूहिक नरसंहार करते हैं और देशवासियों की ओर से उन पर सेना-वायुसेना का प्रयोग करने की मांग उठती है तो ये अपने बौद्धिक अभियानों – हस्ताक्षर अभियान, प्रेस वक्तव्य, लेख आदि के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाते हैं और नक्सलियों के बचाव में तर्क गढ़ने लगते हैं।

नक्सलवाद की समस्या से केवल जंगलों में नहीं निपटा जा सकता, क्योंकि वे केवल जंगलों में ही नहीं रहते हैं। बल्कि शहरों में वे छद्म रूप से सक्रिय हैं। जंगल के नक्सली सिर्फ भौतिक हमला करते हैं जबकि ये बुद्धिजीवी मानसिक हमला करते हुए युवाओं का ब्रेनवाश करते हैं और उन्हें नक्सली बनाते हैं। तभी हमारे विश्वविद्यालयों में छात्र 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' का नारा लगाने का दुस्साहस करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि 'शहरी नक्सली' को भी बेनकाब करते हुए उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। ■

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का जुलाई 2018 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह अंक अभाविप : नयी दृष्टि, नया स्वरूप, दूरस्थ शिक्षा, शहरी नक्सली, अमेरिका - दक्षिण कोरिया संबंध, गुरु पूर्णिमा आदि पर महत्वपूर्ण लेख राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक में पारित प्रस्ताव समेत विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए है। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'

26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,

नयी दिल्ली - 110002.

फोन : 011-23216298

✉ chhatrashakti.abvp@gmail.com

📘 www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti

🐦 www.twitter.com/chhatrashakti1

सोशल मीडिया पर बढ़ता अमर्यादित भाषा का प्रयोग

सोशल मीडिया एक ऐसा आधुनिक मंच है जिससे हम अपने विचारों को साझा करने, एक दूसरे से जुड़ने, लोगों को प्रेरित करने तथा किसी बात को कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में विचारों का प्रवाह सबसे तीव्र गति से होता है। लेकिन वर्तमान सन्दर्भ में सोशल मीडिया की परिभाषा बदल रही है। आज सोशल मीडिया शब्द में मीडिया की शेष है, “सोशल” कहीं नहीं दिखता। सोशल मीडिया पर आये दिन नए नए विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, पलक झपकते ही एक भ्रामक सूचना पूरे समाज में फैल जाती है जिसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं होता। समाजवाद, प्रेम, मित्रता, भाईचारे और ज्ञानवर्धक सूचनाओं की मान्यता को ध्यान में रखकर जन्मा सोशल मीडिया आज पूर्णतः अराजकता एवं हिंसा का रूप ले चुका है। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, किसी अन्य क्षेत्र की बातों को अपने क्षेत्र या समाज से जोड़कर सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में वैमनस्य फैलाया जा रहा है। स्वछंदता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर प्रतिदिन द्वेषपूर्ण टिप्पणी करना व अपने मानसिक विकारों, कुंठाओं की भड़ास निकालना, किसी अन्य धर्म की खिल्ली उड़ाना आम बात हो गयी है। धर्म व मान्यताओं का मजाक उड़ाने के साथ आपसी फूट डालकर समाज में विघटन पैदा कर सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव समाज पर अधिक हावी हो गया है। सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषा के बढ़ते प्रचलन पर “राष्ट्रीय छात्रशक्ति” के लिए उत्कर्ष श्रीवास्तव ने देश के नौजवानों से बात की और उनके विचार जानें, प्रस्तुत है युवाओं के विचार :

सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं, उतने नुकसान भी हैं। आज यह अराजकता, वैमनस्य का अड्डा बनाने की ओर अग्रसर है, लोग एक दूसरे को विघटनकारी पोस्ट भेज रहे हैं, जिससे समाज का कोई सरोकार नहीं होता। फेक अकाउंट बनाकर लोगों को गाली देना, अपशब्दों का प्रयोग करना, समाज की एकता को छिन्न भिन्न करना, अब संकुचित मानसिकता वाले लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में नफरत और जहर फैलाया जा रहा है। सोशल मिडिया पर किसी व्यक्ति को ट्रोल करना आम बात हो गयी है। इसका ताजा उदाहरण विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं, जो सोशल मिडिया की अमर्यादित भाषा का शिकार हो गयीं।

- अखंड प्रताप राय, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी

आजकल किसी भी सोशल साइट्स को देखिये, सभी पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग हो रहा है। वाद विवाद से आगे निकलकर निम्न स्तरीय बातें बढ़ चढ़कर हो रही हैं। लोग अपनी भाषायी मर्यादा भूलकर एक दूसरे को जमकर अपशब्द बोल रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कहीं भी लोग अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया, स्त्रियों के बारे में फूहड़ बातें करना और गंदे - गंदे मैसेज को फैलाने का सबसे आसान माध्यम बन गया है। समाज में आज अधिकतर गलत कार्यों में भी सोशल मिडिया का अहम रोल रहता है।

- **राम प्रकाश शुक्ल**, कानपुर विश्वविद्यालय

सोशल साइट्स का प्रयोग समाज में सभी कर रहे हैं चाहे वो युवा हो या कोई बुजुर्ग। समाज में एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, लेकिन इसका गलत प्रयोग बढ़ रहा है। गलत अकाउंट बनाकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए गलत गलत अफवायें उड़ाई जाती हैं और लोग धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को जमकर अपशब्द बोलते हैं। लोग सोशल साइट्स से जुड़ते हैं जिससे अपने परिवार व दोस्तों से जुड़े रह सके और अपने अच्छे पलों को साझा कर सके; परन्तु सोशल साइट्स पर अपशब्दों, फूहड़ता, अश्लीलता और गलत सूचनाओं के सिवा कुछ नहीं दिखता। इसका दुरुपयोग हमारे समाज के लिए अभिशाप बनता जा रहा है।

- **कविता**, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय

सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, अफवाह फैलाने के मामले में सोशल मीडिया के माध्यम का दुरुपयोग सामने आया। इससे चेतने और सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि बीते समय में इसके भयावह दुष्परिणाम सामने आ चुके हैं। पिछले साल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर निहित स्वार्थी तत्वों ने बंगलुरु रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों में भय पैदा कर दिया था। हाल में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के दौरान भी इसी तरह सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया था। आज एक संप्रदाय के लोगों का दूसरे को गाली देना और दुष्प्रचार करना आम बात है। कुछ साइटों पर होने वाले दुष्प्रचार के कारण पैदा होने वाले ऐसे हालात की कड़ी निगरानी करनी चाहिए।

- **श्वेतांक सिंह**, सिविल इंजिनियर, मुंबई

अगर हम अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें तो क्या हम वास्तव में सोशल मीडिया का उचित इस्तेमाल कर रहे हैं या हम खुद अपने ही हाथों से अपने समाज को दूषित कर रहे हैं? अब तक समाज में लड़ाई झगड़े व्यक्ति विशेष तक सीमित हुआ करते थे मगर सोशल मीडिया ने आपसी झगड़े को भी राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। एक हिन्दू और मुस्लिमान का सोशल मीडिया पर आपस झगड़ना महज दो व्यक्ति की बात नहीं बल्कि देश में मौजूद सम्पूर्ण हिन्दू और मुस्लिम का झगड़ा बन जाता है जिससे धर्मवादिता पनप उठती है और समाज दो भागों में टूट जाता है। सोशल साइट्स पर गलत भाषा का प्रयोग बेहद चिंताजनक है और इस विषय पर समग्र चिंतन करने की नितांत आवश्यकता है।

- **गीता सैनी**, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, दि

परिषद् गतिविधियां



अभाविप, बिहार द्वारा आयोजित छात्रसंघ के निर्वाचित छात्र नेता सम्मेलन का उद्घाटन करते केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्रीनिवास, महामंत्री आशीष चौहान, उप-मुख्यमंत्री (बिहार) सुशील मोदी व अन्य



एनएसयूआई की छात्रा कार्यकर्ता के द्वारा लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोप में धिरे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करने एवं छात्रा कार्यकर्ता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते अभाविप कार्यकर्ता

‘सेल्फी विद कैम्पस’ कार्यशाला

